कुछ घटनाए हुई थी। ऐसे मामले जाच के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रैड क्रास समिति के साथ उठाए गए है क्योकि पाकिस्तान ने जेनेवा अभिसमयो का उल्लघन किया है।

औद्योगिक सम्बन्ध और उत्पादकता

349 **श्री नरेन्द्र सिंह** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बढ़ते हुए उत्पादन की दृष्टि से औद्योगिक सम्बन्धो की रूप-रेखा पर पुनर्विचार करने के सम्बन्ध मे और श्रमिको को आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्य पर उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, और

(ख) यदि हा, तो योजना की मुख्य बाते क्या हैं और इस बारे मे अब तक क्या उपाय किये गये है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) हाल ही मे गठित किये गए नियोजको और कर्मकारो के एक कार्यकारी दल ने, अन्य बातो के साथ-साथ औद्योगिक विवादों के तत्काल निपटान के और कर्मकारो को आवश्यक जिन्से उचित मूल्यो पर सप्लाई करने के प्रश्न पर विचार किया। विवादो के हल और सम्बन्धित मामलो के लिए तत्र सबधी ठोस प्रस्ताव सूचित करने हेतु कर्मकारो के प्रतिनिधियो की फिर बैठक होगी ताकि कार्यकारी दल की अगली बैठक मे जिसके शीघ्र ही होने की सम्भावना है, उन पर विचार-विमर्श कर सके। नियोजको के प्रतिनिधियो ने सरकार के विचारार्थ उनके द्वारा उचित मूल्य दूकानो का जाल सा बिछाने की दिशा मे उठाए जाने वाले ठोस कदम सुझाना स्वीकार किया है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में युद्ध विराम प्रस्ताव पर मतदान

350 **श्री नरेन्द्र सिंह .**
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सयुक्त राष्ट्र संघ मे भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के प्रस्ताव पर भारत के पक्ष मे तथा विरोध मे किन-किन देशों ने मतदान किया और कौन से देश तटस्थ रहे,

(ख) किन देशो ने आक्रमणकारी पाकिस्तान को सक्रिय समर्थन दिया और क्या भारत सरकार का इन देशो के प्रति अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने का विचार है, और

(ग) यदि हा, तो इसका स्वरूप क्या होगा ?

विदेश मत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) स (ग). भारत-पाक सघर्ष के दौरान युद्ध-विराम सबधी जो प्रस्ताव महासभा ने पास किया था उसके पक्ष मे 104 मत आए थे और विपक्ष मे 11, 10 देशो ने मतदान नही किया था और 6 देशो ने मतदान मे हिस्सा ही नही लिया था

विपक्ष मे	भारत, सोवियत समाजवादी गणतत्र संघ, बायलोरशा, एस० एस० आर०, चेकोस्लोवाकिया, क्यूबा, बलगारिया, भूटान, हंगरी, पोलैंड, यूक्राइन, एस० एस० आर० और मंगोलिया।
मतदान न करने वाले देश :	अफगानिस्तान, चिली, डेनमार्क, फ्रांस, मलावी, ओमान, डेनेगल, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम।
मतदान मे हिस्सा न लेने वाले देश :	बर्मा, इक्वीटोरियल गिनी, लेसोथो, माल्दीव, गिनी और मारीशस।

इस प्रस्ताव के पक्ष में भारी बहुमत वस्तुतः भारत विरोधी मत का प्रतीक नहीं है बल्कि अधिकांश सरकारों की इस मनोवृत्ति का सूचक है कि जब कहीं कोई लड़ाई छिड़ जाती है तो वे युद्ध-विराम और सैनिकों की वापसी के आम फारमूले को स्वीकार कर लेना चाहते है। बहरहाल, इसमें स्थिति के मूल कारण को अनदेखा किया गया था।

21 दिसम्बर, 1971 के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के सदर्भ मे संयुक्त राष्ट्र महासभा के मतदान का महत्व समाप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त अतर्राष्ट्रीय समुदाय विद्यमान यथार्थ को और मानवीय स्वाधीनता और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धान्तों की रक्षा में भारत ने जो कार्रवाई की है, उसे अधिकाधिक स्वीकार कर रहा है। इन परिस्थितियो मे, उन देशो का नाम बताना मुनासिब नही होगा जिन्होंने पाकिस्तान को "सक्रिय सहायता" दी है। बहरहाल, भारत के लिए विशेष महत्व के मामलों पर विभिन्न देशो ने जो रवैया अपनाया है उस पर उनके साथ सबध स्थापित करने मे हमेशा ध्यान रखा जाता है।

Release of US secret Papers by Columnist Jack Andersan regarding Indo-Pak War

351. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI :
SHRI S. M. BANERJEE :

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Columnist Jack Andersan released to the Press in January, 1972 the "Secret Sensitive" minutes of the white House strategy sessions on the Indo-Pak war ;

(b) if so, the important features thereof ; and

(c) the reaction of Government of India thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) yes Sir, The American columnist Jack Andersen published in January, 72 what he described as the minutes of three meetings of Washington's Special Action Group presided over by Dr. Henry Kissinger, President Nixon's Adviser on National Security. These meetings related to the Indo-Pak war.

(b) An important feature of these papers is the revelation that President Nixon is alleged to have personally given orders that US policy should be tilted towards Pakistan. While official spokesmen of the US government were maintaining that the United States was follwing an evenhanded policy towards India and Pakistan. Another revelation is that the US government was reported to be seriously considering provision of military supplies to Pakistan through third countries.

(c) If these reports are correct and they have not been contradicted it seems that the US government followed an anti-India policy without keeping in view the correct facts and the realities of the situation in the sub-continent

Construction of office building for Employees Provident Fund Organisation.

352. SHRI R. P YADAV : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the reasons why early action has not been taken to construct the regional offices of the Employees' Provident Fund Organisation in various States in the past, and

(b) the places, where the Regional Offices have been constructed, the amount spent on the construction of the buildings, the cost of the land and the rent paid towards the hiring of the buildings of the Regional Offices during the last three years of all the regional Headquarters ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) :The Provident Fund authorities have reported as under :-

(a) and (b) . The Employees' Provident Fund Organisation has been making efforts to procure land for the construction of office buildings and staff quarters in various places where their regional offices are located.